भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4880
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

निपुण भारत के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

†4880. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी जिलों विशेषकर बिहार में वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में निपुण भारत के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार निपुण भारत के अंतर्गत विशेषकर कक्षा एक से तीन के बच्चों की वैयक्तिक अधिगम प्रगति का पता किस प्रकार लगा रही है;
(ग) पिछड़ रहे बच्चों को लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में, विशेषकर बिहार राज्य में सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने दिनांक 5 जुलाई, 2021 को "बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत मिशन (एनबीएम))" नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक रूप से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप

इस मिशन की स्थापना केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में की गई है - जो स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। समग्र शिक्षा के तहत, बिहार राज्य सहित सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनबीएम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

एनबीएम के तहत, कई प्रकार के प्रणालीगत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और बिहार राज्य सहित पूरे देश में निम्नलिखित प्रगति की गई है:

(i) कक्षा-1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' 'विद्या प्रवेश' दिनांक 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया था। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि (बालवाटिका, आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी), घर पर, निजी प्ले स्कूल आदि) से कक्षा-1 में आने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों का कक्षा-1 में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। यह एक आनंदमय और उत्साहजनक वातावरण में खेल आधारित, आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त अधिगम के अनुभव प्रदान करता है जिससे बच्चे में पूर्व-साक्षरता, पूर्व-संख्यात्मक ज्ञान, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए समग्र विकास होता है। यह कार्यक्रम बिहार सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 से अब तक लगभग 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। बिहार राज्य में विद्या प्रवेश मॉड्यूल के लाभार्थी छात्रों की संख्या नीचे दी गई है।

	कार्यान्वित स्कूलों की संख्या			**कुल लाभान्वित छात्र**		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**
बिहार	65,920	67,657	65,309	20,00,000	15,23,411	12,95,231

(ii) आधारभूत स्तर पर अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए, 20 अक्टूबर, 2022 को आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) जारी की गई थी, जो पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अधिगम शिक्षण सामग्री (एलटीएम), आदि के लिए एक संरचना प्रदान करती है।

(iii) 3-8 वर्ष की आयु के लिए 53 प्ले-आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री का एक सेट जादूई पिटारा (जेपी) 20 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध, जेपी में खिलौने, पहेलियाँ, कहानी कार्ड, फ्लैशकार्ड और शिक्षक पुस्तिकाएं शामिल हैं। इसका डिजिटल विस्तार, ई-जादूई पिटारा, दिनांक 10 फरवरी 2024 को शुरू किया गया जिसके तहत बच्चों, शिक्षकों और माता-पिता का सहयोग करने के लिए 22 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी कहानियाँ, गतिविधियाँ, गाने और एआई-आधारित

बॉट-कथा सखी, टीचर तारा और पेरेंट तारा की व्यवस्था है। एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित, ये पहल आधारभूत चरण का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

(iv) कम से कम 10,000 की आबादी द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषाओं में एफएलएन के लिए 121 स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में प्राइमर (मार्च, 2024 में शुरू किए गए) विकसित किए गए हैं। बिहार राज्य के लिए प्राइमर का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध है:

राज्य	राज्यवार प्राइमर	प्राइमर का नाम	अनुसूचित/गैर अनुसूचित भाषा	जनजातीय/गैर जनजातीय भाषा
बिहार	2	मैथिली	अनुसूचित	गैर जनजातीय
		माल्टो	गैर-अनुसूचित	जनजातीय

(v) बालवाटिका-3 से लेकर कक्षा-2 तक के एफएलएन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के आधार पर अधिगम के परिणामों के आधार पर लक्ष्य तैयार किए गए हैं।

(vi) भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र, परख द्वारा संचालित परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से देश भर में अधिगम और शिक्षा परिणामों को मापने के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर आकलन करती है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक शैक्षिक चरण, अर्थात आधारभूत, प्रारंभिक और चरण मध्य के अंत में छात्रों की अधिगम की दक्षताओं का मूल्यांकन करना है। नवीनतम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2021 और पीआरएस 2024 के दौरान आधारभूत स्तर पर राज्यवार औसत अंकों का तुलनात्मक विश्लेषण निपुण भारत मिशन की गहनता और प्रभाव को दर्शाता है।

देश भर में निपुण भारत मिशन की सफलता को दर्शाते हुए छात्रों की अधिगम की उपलब्धियों में सुधार हुआ है। यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 में बच्चों का प्रदर्शन शहरी और निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर है, जो पिछले सर्वेक्षण के अधिगम के परिणामों में स्पष्ट सुधार का संकेत मिलता है। इसे https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर एक्सेस किया जा सकता है।

(vii) समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) को छात्र की प्रगति का बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यह शिक्षाविदों से परे सह-

पाठ्यक्रम और सामाजिक-भावनात्मक विकास को शामिल करता है। इन मूल्यांकनों से अनुभव साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करती है, जिससे सभी क्षेत्रों में समान प्रगति सुनिश्चित होती है।

स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक श्रेणी अंतराल को कम करना समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित बच्चों तक पहुँचा जाता है। योजना समानता और सभी के लिए सार्वभौमिक पहुंच के सिद्धांतों पर कार्यान्वित की जाती है। समग्र शिक्षा योजना के तहत, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्तर पर अतिरिक्त, प्रासंगिक शिक्षण अधिगम सामग्री भी प्रदान कर रहे हैं। समग्र शिक्षा के तहत, अलग-अलग शिक्षण कार्यक्रमों के लिए कमजोर, छात्रों/पिछड़े बच्चों सहित सीडब्ल्यूएसएन के लिए, कक्षा 6 से 12 तक, अधिगम संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किया गया है।

बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2022 में एक राज्य स्तरीय बेसलाइन सर्वेक्षण और वर्ष 2025 में सभी 38 जिलों में कक्षा 2 के छात्रों का मिडलाइन अचीवमेंट सर्वे किया है। बिहार में कक्षा 2 के लिए वर्ष 2022 बेसलाइन और वर्ष 2025 मिडलाइन अचीवमेंट सर्वे के बीच प्रगति आधारभूत अधिगम परिणामों में स्पष्ट सुधार को उजागर करती है जिसमें कक्षा-स्तरीय पाठ को धाराप्रवाह पढ़ने में सक्षम बच्चों का अनुपात 27% से बढ़कर 42% हो गया है, और एकल अंक जोड़ संबंधी प्रश्नों को हल करने में सक्षम लोगों की संख्या 61% से बढ़कर 69% हो गई है, जो निपुण भारत के तहत राज्य के नेतृत्व वाली एफएलएन पहलों के शुरुआती सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

****